SHRI N. K. P. SALVE: If you read (a) part of the question, (b) is the correct answer to the (a) part... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: Dr. Jichkar has asked as to how they had made a review and there is no reply to that ..(*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, this is a question which cannot be postponed because the answer given by the Minister is incorrect, inadequate and misleading.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over, I will look into the matter and decide in which way we can take up a discussion in the House because the Members are not satisfied... (*Interruptions*)... Now, Question Hour is over.

SHRI YASHWANT SINHA: Are you satisfied as the Deputy Chairman of this House? As the Presiding Officer, are you satisfied with the reply?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Members asked the question. If they are satisfied, I am satisfied, If the Members are not satisfied, I am not satisfied. (*Interruptions*)

Now, Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी-ऋणों का प्रतिकूल प्रभाव

*385. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी ऋणों और भुगतान संतुलन की स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भुगतान शेष की स्थिति कुछ समय से दुसाध्य बनी हुई है तथा विदेशी उधारों के माध्यम से वर्तमान लेखा घाटे के वित्तपोषण की निरंतर आवश्यकता ने विदेशी ऋणों में बढ़ोत्तरी कर दी है। ऋण-परिशोधन की जरूरत के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर अनिवार्य रूप से दबाव पड़ा है। सरकार का लक्ष्य यह है कि कुछ समय के अंतराल में इस चालू लेखा घाटे को कम करते हुए एक प्रबंध योग्य स्तर तक लाकर इस समस्या से निपटा जाए। हमारी अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता में सुधार करके इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, जिससे हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए विदेशी धन की आवश्यकता में कमी करके अपनी आयात संबंधी आवश्यकताओं के लिए अदायगी कर सकते हैं। सरकार का विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है जिससे चालू घाटे के कुछ भाग का वित्तपोषण ऋण की स्थिति न पैदा करने वाली धनराशियों द्वारा किया जा सके।

चालू लेखा घाटे के अनुमानों तथा घाटे के वित्त पोषण संबंधी साधनों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जो 1990-91 तक उपलब्ध

है तथा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के संबंध में नीचे दर्शाये गये हैं :—

(मिलियन डालर)

	1089-90	1990-91 (तुरंत अनुमान)
चालू लेखा घाटा	5900	7294
वित्तपोषण-निम्नलिखित द्वारा:		
निवल विदेशी सहायता	1856	1806
निवल वाणिज्यिक उधार	1744	693
निवल अनिवासी भारतीय जमा राशियां	1467	117
निवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	-877	1214
अन्य पूंजीगत निवल	970	2186
आरक्षित भंडार उपयोग	740	1278

(ग) अपनाए गए उपायों की श्रंखला में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता और निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए व्यापार नीति में सुधार।

(ii) उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की शुरुआत जिसके अंतर्गत आयात लाईसेंस के बोझ को काफी हद तक हटा दिया गया है तथा विदेशी मुद्रा अर्जन के सभी माध्यमों को जोरदार प्रोत्साहन दिया गया है ;

(iii) मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए समुचित राजकोषीय और मौद्रिक उपाय;

(iv) विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों में बढ़ोत्तरी जिससे अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि की जा सके तथा विदेशी क्षेत्र में लेन देन करना आसान हो सके।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, मुद्रा स्फीति की दर में कमी आई है, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों में वृद्धि हुई है तथा विदेशी मुद्रा के विनिमय में किए जाने वाले हवाला के आकर्षण में कमी हुई है। सामान्य मुद्रा क्षेत्रों से संबंधित निर्यात निर्यात अर्जन की गति अभी तक कुछ धीमी रही है लेकिन आशा है कि वर्ष के दौरान इसमें पर्याप्त तेजी आ जाएगी।

Implementation of New Export-Import Policy

*386. SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what are the salient features of the new Import-Export Policy announced by Government in April 1992;

(b) whether it is a fact that Government have failed to issue notification necessary to give effect to the policy; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRY AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN): (a) The new Export and Import Policy